[This question paper contains 10 printed pages.]

6342

Your Roll No. .....

## LL.B.

AS

## III Term

Paper LB-301 - CONSTITUTIONAL LAW - I

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note: - Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी:- इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Answer Five questions including Question No. 1 which is compulsory.

All questions carry equal marks.

अनिवार्य प्रश्न क्रमांक 1 सहित कुल पाँच प्रश्न कीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- 1. Answer briefly any four of the following:
  - (a) Residuary power of legislation
  - (b) Ordinance-making power of President

P.T.O.

- (c) Curative petition
- (d) Doctrine of Territorial Nexus
- (e) Proclamation of Emergency on grounds of war and external aggression

निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर संक्षेप में लिखिए:

- (क) अवशिष्ट विधायी शक्ति
- (ख) राष्ट्रपति की अध्यादेश तैयार करने की शक्ति
- (ग) कष्ट निवारक याचिका
- (घ) राज्यक्षेत्रीय सम्बन्ध का सिद्धान्त
- (ङ) युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात्काल का प्रख्यापन
- 2. (a) Distinguish between a tax, fee and compensatory tax.
  - (b) Can state X impose a sales tax at a lower rate on goods manufactured within the state as compared to goods produced in other states? Answer with reference to constitutional provisions and decided cases.
  - (क) कर, शुल्क और प्रतिकर कर के बीच भेद व्यक्त. कीजिए।
  - (ख) क्या राज्य X अन्य राज्यों में उत्पादित माल की तुलना में राज्य के भीतर विनिर्मित माल पर कम दर पर बिक्री कर अधिरोपित कर सकता है ? सांविधानिक उपबन्धों और विनिश्चित केसों के निर्देश सहित उत्तर दीजिए।

- 3. Discuss the constitutional validity of the following bringing out clearly the principles of Constitutional interpretation you rely on.
  - (a) Parliament enacted the All India Council for Technical Education Act, 1987 for maintaining coordinated development of the technical education system in India. State X enacts a law with respect to private engineering colleges to determine the course structure and functioning of such colleges within the state.

Is this state law valid?

Entry 66, List I: Coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical education.

Entry 25, List III: Education, including technical education, medical education and universities, subject to provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I; vocational and technical training of labour.

(b) A state law banned the use of loud-speakers after 10 p.m. in the interests of reducing noise pollution. Is this law valid?

Entry 31, List I: Posts and telegraphs; telephones, wireless, broadcasting, and other like forms of communications.

Entry 6, List II: Public health and sanitation; hospitals and dispensaries.

साविधानिक निर्वचन के जिस सिद्धान्त पर आप भरोसा करते हैं उस पर स्पष्ट रूप में प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित की साविधानिक विधिमान्यता का विवेचन कीजिए।

(क) संसद ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 को भारत में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समन्वित विकास को बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया था। राज्य X ने राज्य के भीतर प्राइवेट इंजीनियरिंग कालिजों के बारे में उनकी पाठ्यक्रम संरचना और उनका कार्यचालन अवधारित करने के लिए एक विधि अधिनियमित की।

क्या राज्य की यह विधि विधिमान्य है ?

सूची I, प्रविष्टि 66 : उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण ।

सूची III, प्रविष्टि 25 : सूची I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं; श्रमिकों का व्याससायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।

(ख) एक राज्य की विधि द्वारा ध्विन प्रदूषण कम करने के हित में 10.00 बजे रात्रि के बाद लाउड स्पीकरों के उपयोग पर रोक लगा दी गई। क्या उक्त विधि विधिमान्य है?

सूची *I, प्रविष्टि 31* : डाक - तार; टेलीफोन; बेतार प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन ।

सूची *II, प्रविष्टि 6* : लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय ।

- 4. (a) What is meant by repugnancy? Explain with reference to decided cases.
  - (b) Parliament enacted the Hindu Succession Act, 1956, which as originally enacted did not treat wives and daughters of a joint family as coparcenors. In 1990, state Z enacted an amendment to the said law, according to which, unmarried daughters were to be considered as coparcenors. This state amendment received Presidential assent. In 2005 Parliament amended the Hindu Succession Act according to which a daughter by birth was given the right to be a coparcenor. Will this central amendment prevail in State Z? Decide.

Will your answer differ if the Central amendment of 2005 had granted only daughters above the age of 25 the right to become coparcenors, irrespective of whether they were married or not? Decide with the help of relevant case law.

(क) विरूद्ध होने से आपका क्या तात्पर्य है ? विनिश्चित केसों को निर्दिष्ट करते हुए स्पष्ट कीजिए। (ख) संसद ने 1956 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अधिनियमित किया था। प्रारंभ में अधिनियमित हुए उक्त अधिनियम में अविभक्त कुटुम्ब की पित्नयों और पुत्रियों को सहदायिक के रूप में नहीं माना जाता था। 1990 में राज्य Z ने उक्त विधि में एक संशोधन का अधिनियमन किया जिसके अनुसार अविवाहित पुत्रियों को सहदायिक के रूप में मानना होता था। इस राज्य संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमित प्राप्त हो गई। 2005 में, संसद ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को संशोधित कर दिया जिसके अनुसार जन्म की पुत्री को सहदायिक होने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। क्या उक्त केन्द्रीय संशोधन राज्य Z में अभिभावी होगा ? विनिश्चय कीजिए।

यदि केन्द्र का 2005 का संशोधन केवल 25 वर्ष से अधिक की पुत्रियों को सहदायिक होने का अधिकार बिना इस पर विचार किये दे देता कि क्या वे विवाहित हैं या नहीं हैं तो क्या इससे आपके उत्तर में कोई अन्तर आएगा ?

सुसंगत निर्णय विधि की सहायता से विनिश्चय कीजिए।

5. (a) Mr. C files a writ petition under Art. 226 before a High Court alleging violation of fundamental right to freedom of religion. After consideration, the High Court dismisses his petition. Dissatisfied, Mr. C now seeks to move the Supreme Court under Art. 32 of the Constitution for obtaining relief on the same grounds. Will he succeed? Decide.

- (b) Is consultation with the 'collegium' of judges necessary when appointing a permanent judge of a High Court, if the process had already been complied with at time of initial appointment of the same person as an additional judge of the High Court? Decide.
- (क) मि॰ C ने उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के उल्लंघन का अभिकथन करते हुए फाइल की। विचार करने के उपरान्त, उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। सन्तुष्ट न होने पर मि॰ C अब उन्हीं आधारों पर अनुतोष प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में समावेदन करना चाहता है। क्या वह सफल होगा ? विनिश्चय कीजिए।
- (ख) क्या जजों के 'कॉलीजियम' से उच्च न्यायालय के स्थायी जज को नियुक्त करते समय परामर्श फिर भी आवश्यक है यदि उसी व्यक्ति की उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जज की प्रारंभिक नियुक्ति के समय उक्त प्रक्रिया का पहले ही अनुपालन कर दिया गया हो ? विनिश्चय कीजिए।
- 6. The Governor of a State Y submits a report to the central government stating that there is breakdown of law and order in the state and recommending imposition of President's Rule there. The President issues a Proclamation under Art 356 even though the Chief

Minister of the state enjoys support of the majority of the legislature assembly.

What is the extent of judicial review in such matters if the imposition of President's Rule were to be challenged?

Can the Proclamation be set aside and the government restored? Decide citing precedents.

Y राज्य का राज्यपाल राज्य में विधि तथा व्यवस्था के ठप हो जाने का उल्लेख करते हुए तथा वहां राष्ट्रपति का शासन अधिरोपित करने की सिफारिश करते हुए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अधीन प्रख्यापन जारी कर देते हैं हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री को विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

यदि राष्ट्रपति शासन के अधिरोपण को आक्षेपित किया जाना है तो ऐसे गामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन किस सीमा तक होता है ?

क्या उक्त प्रख्यापन को अपास्त किया जा सकता है तथा सरकार को बहाल किया जा सकता है ? पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए विनिश्चय कीजिए।

- 7. Answer the following with the help of decided cases:
  - (a) Can the President appoint as Prime Minister a person who is not a member of either House of Parliament?

(b) A prisoner awaiting death sentence files a mercy petition before the President. The government recommends rejection of this petition. Can the President refuse to abide by such advice and grant pardon to such a person on the ground that capital punishment is against constitutional principles? Decide.

विनिश्चित केसों की सहायता से निम्नलिखित का उत्तर दीजिए:

- (क) क्या राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है।
- (ख) मृत्यु दडादेश की प्रतीक्षा करने वाला एक बन्दी राष्ट्रपित के सामने दया याचिका प्रस्तुत करता है। सरकार इस याचिका की अस्वीकृति की सिफारिश करती है। क्या राष्ट्रपित ऐसी सलाह मानने से इंकार कर सकते हैं तथा उक्त व्यक्ति को इस आधार पर क्षमा प्रदान कर सकते हैं कि मृत्यु दंड साविधानिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। विनिश्चय कीजिए।
- 8. Discuss the Constitutional validity of the following:
  - (a) Under a treaty entered into with the adjacent country, the Executive cedes a part of the territory of India and its territorial waters on the ground that this has the assent of the State Legislature whose territory is thereby diminished.

(b) Parliament by law renames a state without receiving the approval of the affected state legislature.

निम्नलिखित की सांविधानिक विधिमान्यता का विवेचन कीजिए:

- (क) एक पड़ोसी देश के साथ की गई संधि के अन्तर्गत कार्यपालक भारत के राज्यक्षेत्र के एक भाग तथा राज्यक्षेत्रीय समुद्र को इस आधार पर अध्यर्पित कर देता है कि इसको उस राज्य के विधानमंडल की अनुमित प्राप्त है जिसका राज्यक्षेत्र इसके द्वारा घटने जा रहा है।
- (ख) संसद विधि द्वारा एक राज्य को उक्त राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किए बिना पुनर्नामित कर देती है।